

but we are trying to get it and certain improvement is there but I do agree with the hon. Members that much more is to be made and particularly I am concerned about the complaints and about the shortages. If any hon. Members bring them to my notice, I can assure them that I will look into them and corrective action will be taken.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House now stands adjourned till 2-05 p.m.

13.05 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till five minutes past Fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past Fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) CONSTRUCTION OF A BRIDGE OVER YAMUNA RIVER IN DELHI NEAR INTER-STATE BUS TERMINAL.

SHRI H.K.L. BHAGAT (East Delhi): With your kind permission, I raise the following matter of urgent public importance.

It is a matter of regret that the construction of a new bridge over the Yamuna river in Delhi near the inter-State bus terminal which was sanctioned by the Congress Government in 1976, has not started yet, causing great and continued hardship and inconvenience to lacs of people and thousands of vehicles, which have to cross Yamuna every day due to traffic jam and congestion. Construction of the bridge on priority basis is a necessity not only for the people living in trans-Yamuna area, the people of Delhi but also people of Uttar Pradesh and other areas States. Urgent attention of the Government to the matter is required. The work should start quickly and a time-bound programme for completion of the bridge should be fixed.

(ii) ERA SEZHIYAN COMMITTEE REPORT ON THE WORKING OF LIC.

SHRI R.K. MHALGI (Thane): The Era Sezhiyan Committee appointed by the Government to review the working of LIC has submitted their report long ago. The Committee have made a number of important and useful suggestions and recommendations.

Lakhs of LIC policy holders are waiting for the decision to be taken by the Government thereon. The recommendations of group-term policy shall receive well as it provides a kind of block insurance to large section of people in the un-organised sector.

I, therefore, urge upon the Government to take as immediately as possible the decision on the said Committee's Report or at least on some of the important recommendations of the Report.

(iii) DRINKING WATER PROBLEM IN RAJASTHAN.

श्री दौलत राम सारण (चुरू): राजस्थान के अधिकांश भागों में दो वर्षों से भयंकर अकाल है। कुछ स्थानों में 3-4 वर्ष से अकाल है। यह अकाल वर्षा की कमी के कारण है। वर्षा के अभाव के कारण मनुष्यों और पशुओं के लिए पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। राजस्थान के लगभग 34,000 गांवों में से 24,000 गांवों में पीने के पानी की कमी है। 11,000 गांवों में पीने योग्य पानी ही नहीं है। वहां खारा पानी है, जहरीला अथवा अस्वास्थ्यकर पानी है। लाखों पशु जहरीला पानी पी कर प्रतिवर्ष मर जाते हैं और अस्वास्थ्यकर पानी पीने से अनेक क्षेत्रों में कुबड़ापन आदि असाध्य रोगों से हजारों लोग पीड़ित हैं। पानी के अभाव से पीड़ित इन गांवों के लोग पांच से दस मील की दूरी से प्रतिदिन ऊंटों पर पीने के लिए पानी लाते हैं अथवा गांवों को खाली करके पानी वाले स्थानों पर चले जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकार द्वारा निर्मित ग्राम जल

जल प्रदाय योजनायें ग्रामवासियों और उनके पशुओं को पीने की पानी की सुविधा प्रदान करने में बिल्कुल असफल हैं। ये योजनाएं दोषपूर्ण होने के कारण पूरे पानी की पूर्ति नहीं कर पाती। इन योजनाओं में पिछली जन गणना के आधार पर केवल मनुष्यों के लिए ही पानी का अनुमान लगाया गया है। मनुष्यों की बढ़ी हुई संख्या भी योजना अनुमानों से कहीं अधिक है और पशुओं को तो इन योजनाओं में बिल्कुल ही श्रुमार नहीं किया गया है। परन्तु ग्रामवासियों की आय के खास साधन पशु ही हैं। लगभग पांच पशु प्रति व्यक्ति का औसत है। इन के लिए इन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में पानी की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कहा जाता है कि केवल मनुष्यों के लिए ही पानी दिया जा सकता है, परन्तु जिन गांवों में ये योजनाएं बनाई गई हैं, उन में पशुओं को पानी पिलाने का अन्य कोई स्रोत नहीं है और इन पशुओं के बिना ये ग्रामवासी जिन्दा नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी आजीविका के ये पशु ही आधार हैं। उनके सामने पानी का संकट जल प्रदाय योजना वाले गांवों में समाधान के स्थान पर और गम्भीर हो गया है। अनेक योजनाओं के स्रोत ही समाप्त हो गए हैं। कई योजनाओं में सम्मिलित गांवों तक पानी पहुंचा ही नहीं है, जबकि योजना बने हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। अधिकांश योजनाओं में मशीन की खराबी बिजली की कमी, डीजल का अभाव या अन्य कारण बता कर ये अनेक दिनों तक बन्द पड़ी रहती हैं। उसके समाधान के लिए बनाई गई दोषपूर्ण ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में सुधार कर के योजना अनुमानों में मनुष्यों की बढ़ी हुई संख्या और पशु संख्या को

सम्मिलित कर के जल प्रदाय के लिए सही योजनाएं बनाई जाएं और पुरानी योजनाओं में इस संशोधन को पूरा कर के उन्हें ठीक किया जाए। तभी ये योजनाएं पानी की समस्या का समाधान करने में सफल एवं उपयोगी हो सकती हैं।

मैं आशा करता हूं कि इस गम्भीर समस्या का समाधान किया जाएगा।

(iv) PROBLEMS OF COCOONS AND LAC GROWERS IN BIHAR

SHRI N.E. HORO (Khunti): Lakhs of Tribals and other weaker sections of the population in Chotanagpur plateau region are engaged in rearing silk cocoons and stick lac. These two items are export commodities and earn considerable foreign exchange for the country.

Silk cocoons and lac are grown on trees which generally backing to Government forests. Tribal and other communities had traditional rights to rear them freely without any interference from the Forest Department. In Bihar these traditional rights were recorded rights in the Record of Rights of tenants.

Now, the Government of Bihar in the Forest Department have put restrictions on rearing Cocoon and Lac and are demanding rearing fees.

The Tribals and other growers of Cocoon and Lac are facing financial loss due to erratic market prices controlled by the traders and middlemen. Many growers have taken loans from Banks and they are in arrears in repayment of loans. The growers are not getting remunerative prices and they are compelled to sell their produce of cocoon and lac at throw away prices at great financial loss to them.

I draw the attention of the Commerce Ministry to these facts and demand—